प्रदेश के मंत्रालयिक कर्मचारी बीते 56 दिनों से अपनी मांगों को लेकर दिन-रात सड़क पर डटे हुये हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में मंत्रालयिक कर्मचारी, सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करने के लिये राजमहल चौराहे पर एकत्रित हुए। लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। गौरतलब है कि, मंत्रालयिक कर्मचारी पिछले 63 दिनों से हड़ताल पर हैं तथा 56 दिन से महापड़ाव डाले हुए हैं। इस दौरान 5 मंत्रालयिक कर्मचारियों की मौत हो चुकी है तथा कई कर्मचारी गंभीर बीमारियों से पीड़ित चल रहें हैं। तपती धूप में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे मंत्रालयिक कर्मचारियों का कहना है कि, गांधीवादी कहलाने वाले मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता के कारण आज हम सड़कों पर खुले आसमान के नीचे दिन-रात गुजार रहे हैं। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो, हम मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे।

मैडिकल कॉलेजों में एडमिशन, एक ही राष्ट्रीय नीति अपनाने के विरोध में है तमिलनाडु

तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, तमिलनाडु में मैडिकल कॉलेजों में सबसे अधिक सीटें हैं और हम नहीं चाहते कि, दूसरे राज्यों के छात्र हमारी सीटों पर कब्जा करें

■ **उन्होंने कहा कि, तमिलनाडु सरकार पहले ही इसका विरोध कर चुकी है। यदि नैशनल मैडिकल काउन्सिल (एन.एम.सी.) तमिलनाडु की सीटों के लिए अन्य राज्यों के लिए भी काउन्सलिंग आयोजित करता है, तो इससे तमिलनाडु के छात्रों के हित प्रभावित होंगे।**

चेन्नई, 12 जून (वार्ता)। स्वास्थ्य मंत्री मा.सुब्रमण्यम ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु मैडिकल प्रवेश के लिए राष्ट्रव्यापी सामान्य काउंसलिंग का कड़ा विरोध करेगा।

सुब्रमण्यम ने यहां मद्रास मैडिकल कॉलेज के 187वें स्नातक दिवस को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कभी भी मैडिकल सीटों के लिए कॉमन काउंसिलिंग की अनुमति नहीं देंगे। यदि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन.एम.सी.) राज्यों के लिए भी काउंसलिंग आयोजित करता है, तो तमिलनाडु के छात्र प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार पहले ही इसका विरोध कर चुकी है। राज्य में चिकित्सा शिक्षा की सबसे अधिक सीटें हैं और अन्य राज्यों के गैर-तमिलों को इसका लाभ मिलेगा। इससे यहां के छात्रों की प्राथमिकता खत्म हो जाएगी।

केन्द्र सरकार ने पिछले महीने ने एक मसौदा भेजा था जिसमें कहा गया था कि वह मैडिकल सीटों के लिए एक कॉमन काउंसलिंग आयोजित करेगी। पत्र के जवाब में तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने केंद्र सरकार को एक आपत्ति पत्र भेजा।

उन्होंने कहा कि इससे पहले, संबंधित राज्य सरकारें अखिल भारतीय कोटा के लिए दी गई 15 प्रतिशत सीटों के बाद 85 प्रतिशत सीटों के लिए एम.बी.बी.एस. और बी.डी.एस. प्रवेश के लिए काउंसलिंग आयोजित करती थीं।

उन्होंने कहा , हमने पहले ही कॉमन काउंसलिंग पर आपत्ति जताई है और मुख्यमंत्री कभी भी केंद्र सरकार को राज्य की सीटों के लिए भी काउंसलिंग आयोजित करने की अनुमति नहीं देंगे।

‘कुछ मार्गों पर ट्रेन के फर्स्ट ए.सी. व विमान का किराया एक बराबर है’

केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुये सबूत के तौर पर दिल्ली से बैंगलुरु का किराया चार्ट प्रस्तुत किया

■ **ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि, यू.पी.ए. के शासन काल में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है।**

■ **ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वीकार किया कि, इन दिनों एयरलाइन्स एजेंसियों ने कुछ मार्गों पर यात्री किराये में बढ़ोतरी की है। परंतु यह ज्यादातर उन मार्गों पर हुई है जहां पहले गोफर्स्ट एयरलाइन्स की उड़ानें परिचालित होती थी। मामला मेरे संज्ञान में आते ही उड्डयन मंत्रालय में इस मामले में हस्तक्षेप किया है।**

नई दिल्ली, 12 जून (वार्ता)। केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश की विभिन्न एयरलाइनों के कुछ चुनींदा सेक्टरों में किरायों में अनुपात से अधिक बढ़ोत्तरी के कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए आज कहा कि विपक्षी पार्टी तथ्यों का चुनींदा इस्तेमाल करके अपने स्वार्थी राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप जनता की धारणा को प्रभावित करना चाहती है।

सिंधिया ने ट्विटर पर कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के दिल्ली बेंगलुरु सेक्टर पर किराया अनुपात से अधिक होने के आरोप पर पलटवार किया और किराया चार्ट साझा करके कहा कि दोनों शहरों के बीच हवाई किराया रेलवे में एसी प्रथम श्रेणी के किराये के बराबर हैं।

सिंधिया ने भी ट्विटर पर जवाब में कहा, के.सी. वेणुगोपाल तथ्यों को मनमर्जी से प्रस्तुत कर रहे हैं, और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के शासन के दौरान नागरिक उड्डयन के साथ किये गए सौतेले व्यवहार को भूल गये हैं। उन्होंने कहा कि यह सही है कि हवाई किराए में वृद्धि हुई है, पर यह ज्यादातर उन मार्गों पर हुई है जहां पहले गोफर्स्ट एयरलाइन्स की उड़ान परिचालित होती थी। मंत्रालय ने न केवल इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लिया, बल्कि एयरलाइनों को स्व-विनियमन के लिए सख्त सलाह भेजकर हस्तक्षेप भी किया। नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) इस पर कड़ी नजर रख रहा है। किराए में 60 प्रतिशत तक की कमी आई है, और इसके और घटने की संभावना है।

नागर विमानन मंत्री ने कहा कि मंत्रालय के कदम उठाने के बाद प्रमुख सेक्टरों में किराये में काफी गिरावट आई है। उन्होंने इसके बारे में एक चार्ट भी साझा किया। उन्होंने कहा, एक वकील के रूप में, आपसे अधिक मेहनती होने की अपेक्षा की थी। राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एन.सी.एल.टी.) के अधिस्थगन आदेश के अनुसार, गोफर्स्ट एयरलाइन को दिए गए हवाई अड्डे के स्लॉट फ्रीज कर दिए गए हैं और उन्हें फिर से आवंटित नहीं किया जा सकता है। हालांकि इन रूटों पर उड़ान भरने के लिए एयरलाइंस को 68 अतिरिक्त रूट आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस की क्षमता पर 2014 के बाद से बेड़े के आकार में 75 फीसदी की वृद्धि हुई है (400 से 700 विमानों तक)। अधिकांश घरेलू एयरलाइनों के पास एक स्वस्थ ऑर्डर-बुक है, और वे अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर परिचालन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा शुल्क और अन्य शुल्क एयरलाइन के कुल खर्च का लगभग 7 प्रतिशत ही बनते हैं।

अमेरिका के नाइट क्लब में गोलीबारी

ह्यूस्टन, 12 जून (वार्ता) अमेरिका के टेक्सास प्रांत के सबसे बड़े शहर ह्यूस्टन में रविवार को नाइट क्लब में हुई गोलीबारी में छह लोग घायल हो गए है।

पुलिस प्रमुख ट्रॉय फिनर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, यहां क्लब की पार्किंग में हुई गोलाबरी में छह लोग घायल हुए है।

■ **टैक्सस प्रांत के सबसे बड़े शहर ह्यूस्टन में रविवार को नाइट क्लब में हुई इस गोलीबारी में 6 लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए हैं।**

उन्होंने बताया कि रविवार तड़के हुई गोलीबारी में घायल हुए लोगों की उम्र करीब 20 से लेकर 30 के बीच की है। उन्होंने बताया कि एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई हैं।

उन्होंने कि हमलावर कितने थे यह पता नहीं चल सका हैं। किसी भी संदिग्ध को हिरासत में नहीं लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय मीडिया के अनुसार ह्यूस्टन में शुक्रवार की रात को भी गोलीबारी की घटना सामने आयी थी।

राम मंदिर के ग्राउण्ड फ्लोर का काम अंतिम चरण में, अक्टूबर में हो जायेगा तैयार

अगले साल जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी संभावना है

■ **राम मंदिर तीन मंजिला होगा, गर्भ ग्रह में राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल जनवरी में की जाएगी। इसके लिए फिलहाल तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बताया गया है कि, मकर संक्रांति के बाद यह आयोजन रखा जाएगा।**

अयोध्या, 12 जून। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम अब अंतिम चरण में है। ऐसे में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे। जहां पर उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। उम्मीद की जा रही है कि राम मंदिर का भूतल इसी साल अक्टूबर तक बन कर तैयार हो जाएगा। वहीं अगले साल जनवरी में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर निर्माण की मौके पर जाकर जानकारी ली। निर्माण कार्य की हर दिन निगरानी की जा रही है और काम तेजी से चल रहा है।

राम मंदिर तीन मंजिला होगा, गर्भ ग्रह में राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल जनवरी में की जाएगी।

इसके लिए फिलहाल तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बताया गया है कि मकर संक्रांति के बाद यह आयोजन रखा जाएगा। साथ ही इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा।

गौरतलब है कि, राम मंदिर 380 फ़ीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। वहीं कुबेर टीले पर शिव मंदिर और जटायु भक्तों को आकर्षित करेगा। राम मंदिर में सागौन की लकड़ी के 46 दरवाजे होंगे। साथ ही गर्भ गृह का दरवाजा स्वर्णजड़ित होगा। साथ ही मंदिर में 392 स्तंभ होंगे।

दिवंगत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्टनर, गठबंधन तोड़ने की धमकी दे चुके हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब तमिलनाडु के इस भाजपा नेता ने इच्छा व्यक्त की थी कि पार्टी अकेले के दम पर ही चुनाव लड़े तथा उस समय दोनों पार्टियों के संबंध बहुत खराब स्थिति में पहुँच गये थे। उस समय, भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व ने हस्तक्षेप करते हुये, दोनों दलों में समझौता कराया था।

लेकिन भ्रष्टाचार पर अन्नामलाई के रूख तथा जयललिता का नाम लिये बिना, उनके खिलाफ की गई उनकी टिप्पणी से दोनों मित्र दलों के बीच मानो अपशब्दों की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस इन्टरव्यू में अन्नामलाई ने कहा था कि भ्रष्टाचार को लेकर, कुछ नेता गिरफ्तार हुये तथा कुछ को जेल भी हुई थी, जो कि वस्तुत: एक तथ्य भी है, लेकिन जैसा कि अन्नाद्रमुक तथा कुछ राजनैतिक विश्लेषक कहते है, यह सब कुछ एक रणनीति के तहत हुआ था।

राजनैतिक विश्लेषक सुमंत सी. रमन कहते है कि जयललिता पर अन्नामलाई के बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि, एक नेता जो मर चुका है जिसे आपका सहयोगी दल सम्मानीय मानता है, तमिलनाडु की जनता जिसका आदर करती है, उसके बारे में बुरा बोलना ठीक नहीं है। अन्नामलाई ने जयललिता का नाम लिए बिना उन पर जो बयान दिया है उसे लेकर वरिष्ठ अन्नाद्रमुक नेता और पूर्व मंत्री डी. जयकुमार ने अन्नामलाई पर तीखा हमला बोला और पूछा कि अन्नाद्रमुक बिना भाजपा कहां होगी। वर्ष 2021 के चुनाव में भाजपा ने जो चार सीटें जीतीं थी वो भी अन्नाद्रमुक की मेहरबानी से।

अन्नाद्रमुक नेता ने कहा कि अन्नामलाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने योग्य नहीं है। वे गठबंधन धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नड्डा को स्पष्ट करना चाहिए वरना उनकी पार्टी गठबंधन तोड़ने को मजबूर हो जाएगी।

कुश्ती संघ के चुनाव 4...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आई. के चुनाव 30 जून को कराए जाएंगे लेकिन यह स्पष्ट था कि, इस समय सीमा का पालन करना मुश्किल होगा क्योंकि डब्ल्यू.एफ.आई. की विशेष आम बैठक (एस.जी.एम.) के लिए 21 दिन का नोटिस देना जरूरी है।

डब्ल्यू.एफ.आई. की एस.जी.एम. या ए.जी.एम. (वार्षिक आम बैठक) में चुनाव कराए जाएंगे। ठाकुर ने पहलवानों को आश्वासन दिया था कि सरकार डब्ल्यू.एफ.आई. के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के परिवार के किसी सदस्य या सहयोगी को चुनाव लड़ने की स्वीकृति नहीं देगी जिसके बाद पहलवानों ने 15 जून तक अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। आई.ओ.ए. के सी.ई.ओ. कल्याण चौबे ने न्यायमूर्ति मित्तल कुमार को उनकी नियुक्त की जानकारी दी और इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए कहा।

चौबे ने पत्र में कहा, आई.ओ.ए. को डब्ल्यू.एफ.आई. की कार्यकारी परिषद के चुनाव कराने के लिए कदम उठाने होंगे और डब्ल्यू.एफ.आई. के चुनावों के लिए हमें आपको निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने की खुशी है। आप चुनाव कराने में अपनी मदद करने के लिए एक सहायक निर्वाचन अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं। पत्र के अनुसार, चुनाव डब्ल्यू.एफ.आई. की विशेष आम बैठक में कराए जाने हैं जो चार जुलाई को बुलाई गई है और इसी के अनुसार चुनाव का कार्यक्रम तैयार करना होगा।

इसमें कहा गया, हम आपकी ओर से पद की स्वीकृति की पुष्टि और चार जुलाई को डब्ल्यू.एफ.आई. के चुनावों को लेकर उत्सुक हैं। सूत्रों ने हालांकि कहा कि न्यायमूर्ति मित्तल कुमार स्वयं एस.जी.एम. और चुनावों की तारीख पर फैसला कर सकते हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि वह चार जुलाई को चुनाव कराएं या इसके कुछ दिन बाद। डब्ल्यू.एफ.आई. की 25 मान्यता प्राप्त इकाइयां हैं। प्रत्येक राज्य दो प्रतिनिधि भेज सकता है और प्रत्येक प्रतिनिधि का एक वोट होगा। इस तरह डब्ल्यू.एफ.आई. की निर्वाचन सूची में 50 वोट होंगे। डब्ल्यू.एफ.आई. के संविधान के अनुसार राज्य इकाइयां उनकी प्रतिनिधियों को नामित कर सकती है जो उनकी कार्यकारी समितियों का हिस्सा हैं। यह देखना होगा कि तब क्या होगा जब बृजभूषण से जुड़ा कोई पात्र व्यक्ति चुनाव के लिए नामांकन दायर करेगा। बृजभूषण का बेटा करन डब्ल्यू.एफ.आई. के पिछले ढांचे में उपाध्यक्ष था और वह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ से भी जुड़ा है। उसका दामाद विशाल सिंह बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। दोनों राज्य संस्था के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने के पात्र हैं।

सायक्लोन “बिपरजॉय” से बड़े नुकसान की आशंका

■ **मौसम विभाग के अनुसार सायक्लोन के आगामी 14 जून के बाद पाकिस्तान से होते हुये गुजरात में प्रवेश करने की संभावना है।**

नई दिल्ला, 12 जून (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण उत्पन्न स्थिति की सोमवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की और यह सुनिश्चित करने को कहा कि तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों ले जाने तथा जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सभी उपाय किये जायें।

प्रधानमंत्री ने बैठक में मौजूद केन्द्र तथा गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठायें और वहां बिजली, संचार, स्वास्थ्य , पेयजल आदि सभी सुविधा पहुंचाने के लिए सभी उपाय करें। उन्होंने कहा कि तूफान की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नियंत्रण कक्ष दिन रात काम करे। साथ ही यदि तूफान के कारण कोई नुकसान होता है तो स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए सभी कदम उठाये जायें।

मौसम विभाग की ओर से बैठक में चक्रवाती तूफान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह तूफान 15 जून को गुजरात के तट से टकरा सकता है। इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने तथा भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य सरकारों और संबंधित एजेन्सियों को नियमित बुलेटिन के माध्यम से निरंतर जानकारी दी जा रही है।

बैठक में यह भी बताया गया कि गृह मंत्रालय स्थिति पर नजर रखते हुए निरंतर निगरानी कर रहा है तथा राज्य सरकार और विभिन्न एजेन्सियों के साथ संपर्क बनाये हुए है।

स्टालिन ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विभाग, बैंकिंग और संसद, जो हमें और हमारे लोगों को रोज प्रभावित करते हैं, ये हिंदी को मिल रहे अनुचित महत्व को खत्म कर देंगे। हम अपना टैक्स देते है, विकास में योगदान करते हैं, और हम हमारी समृद्ध विरासत व देश की विविधता पर भरोसा करते हैं। हमारी भाषा को बराबर का दर्जा चाहिए। हम हमारे राज्य में तमिल की जगह हिंदी को लागू करने के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे।

हिंदी थोपे जोने के कड़ा विरोध कर स्टालिन ने साफ संकेत दे दिया है कि चुनावी वर्ष में भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए यह मुद्दा ज्वलंत रखा जाएगा, तमिलनाडु में भाजपा को हिंदी भाषी, उत्तर भारतीय पार्टी माना जाता है। द्रमुक फिर से इस मुद्दे को हवा दे रही है। जिसकी वजह से 1967 में पहली बार कांग्रेस को हरा कर द्रमुक सत्ता में आई थी। संयोगवश उस समय कांग्रेस ने हिंदी थोपने की कोशिश की और कीमत चुकाई। यहाँ तक आज भी कांग्रेस तमिलनाडु में अपने पैर नहीं जमा पाईं है और उसे अन्य द्रविड़ दलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

काफी सहानुभूति जागृत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गलत नहीं किया है तथा वाइट हाउस से जाने से पहले दस्तावेजों को डिक्लासिफाई कर दिया था। पर अभियोग कहता है कि यह सही नहीं है। वे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को बतौर सबूत पेश कर रहे है जिसमें उन्होंने माना है कि दस्तावेज़ अभी भी क्लासिफाइड हैं। ट्रम्प ने कहा है कि इस सबसे वे राष्ट्रपति पद की चुनावी दौड़ से नहीं हटेंगे। रिपब्लिकन पार्टी में उन्हें चुनौती देने वाले एक प्रत्याशी विवेक रामास्वामी ने कहा कि अगर वे 2024 का चुनाव जीते तो ट्रम्प को माफ कर देंगे। कन्जर्वेटिव एन्ट्रेप्रच्योर ने सी.एन.एन. के “स्टेट ऑफ द यूनियन” को लेकर कहा, “इस अभियोग पत्र को पढ़कर तथा तथ्य एव कानून-दोनों की चयनात्मक गलतियों की गहराई में जाने पर, मैं और भी ज्यादा सुनिश्चित हो गया हूँ कि माफी ही सही जवाब है। ...... मैंने यह पाया है कि दस्तावेज बहुत ज्यादा राजनीतिकृत है।”

ट्रम्प को पहला आरोप पत्र मैनहटन ग्रान्ड जूरी ने मार्च में दिया था। इसमें ट्रम्प पर महिलाओं को खामोश रहने के लिये दी गई धनराशि से संबंधित वित्तीय घोटालों तथा प्रचार में नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाये गये थे। ज्ञातव्य है कि यह राशि 2016 के चुनाव से पहले के विवाहेतर-संबंधों के परिणामों से बचने के लिये दी गई थी।

साउथ केरोलिना की रिपब्लिकन प्रतिनिधि नैन्सी मेस, जो ट्रम्प तथा जी.ओ.पी. के अन्य लोगों गी प्राय: आलोचना करती रहती हैं, भी ट्रम्प के बचाव में आ गई हैं।

उन्होंने इन आरोपों के समय पर सवाल खड़े किये तथा कहा कि ये उसी दिन सामने आये हैं, जब कानून-निर्माता एफ.बी.आई. दस्तावेज तक पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि यह बात दर्शाती है कि राष्ट्रपति बाइडन तथा उनका परिवार “पे-टु-प्ले” स्कीम में तभी लग गया था जब वे उपराष्ट्रपति थे।

मेस ने “सनडे मॉर्निंग फीचर्स विद मैरिया बार्टीमोरो” पर कहा, “आप राजनैतिक रूप से डॉनल्ड ट्रम्प से सहमत हों या न हों, पर अधिकांश अमेरिकन जानते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है। एग्ज़िक्यूटिव ब्राँच को हथियार उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि राजनैतिक दुश्मनों को खदेड़ा जा सके।”

दिल्ली में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अंतिम नीति बनने तक बाइक टैक्सी सेवा प्रदाताओं पर कोई कार्यवाही न की जाए। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दिल्ली सरकार की हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर दो याचिकाओं को सुना। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में रैपिडो व उबर को राष्ट्रीय राजधानी में नीति बनने तक बाइक टैक्सी सेवा देने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वह जल्दी ही गाइडलाइन्स बना लेगी।

प्रियंका गांधी ने विशाल रैली से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जोड़ो यात्रा इस क्षेत्र से होकर नहीं गुजर पाई थी।

कांग्रेस 2018 के मध्य प्रदेश चुनावों में जीत गई थी लेकिन कमलनाथ सरकार दो साल बाद, उस समय गिर गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, 22 विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर, भाजपा में चले गये थे। पार्टी छोड़कर जाने वाले अधिकांश लोग भाजपा प्रत्याशियों के रूप में, बड़े आराम से पुनर्निवासित भी हो गये थे।

भाजपा ने राज्य विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह “सॉफ्ट हिन्दुत्व” की राह पर चल रही है।

इन आरोपों का खंडन करते हुये, पार्टी नेता पी.सी. शर्मा ने कहा, “भाजपा भगवान राम को सीताजी से अलग करती है। हम कहते हैं-“जय सियाराम”, वे कहते हैं-“जय श्रीराम”।....वे धर्म की राजनीति करते हैं, हम धर्म का अनुसरण करते हुये राजनीति करते हैं, चाहे भगवान कृष्ण की बात हो, या भगवान राम की। ये सब न्याय के देवता हैं।...हिमाचल और कर्नाटक में क्या हुआ है-भगवान वैसा ही न्याय मध्य प्रदेश में करेगा।”

कर्नाटक में चुनावी गारंटियों की कामयाबी से प्रफुल्लित कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावाधीन मध्य प्रदेश के लिये गारंटियों का पुलिन्दा खोल दिया।

प्रत्येक परिवार की एक महिला को 1500 रू. मासिक भत्ते की घोषणा के साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक परिवार को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जायेगी तथा एल.पी.जी. सिलैण्डर 500 रू. में दिया जायेगा।

प्रियंका ने कहा कि अगर कांग्रेस राज्य की सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन स्कीम वापस लायी जायेगी।

यह बताते हुए कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान, राज्य में बहुत बड़ी संख्या में किसानों के ऋण माफ कर दिये थे, प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो शेष बचे किसानों के कर्ज भी माफ कर दिये जायेंगे।

उन्होंने कहा कि लोग भाजपा को आगे और झाँसे न देने दें।

प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के दौरान किये गये वादों को सदैव पूरा करती आई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में दी गई गारंटियों को राज्य मंत्रिमण्डल में मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंच पर अन्य नेताओं के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद थे।

कोविन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यूज़र्स का डेटा लीक हुआ है, के बाद केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स एवं इन्फॉर्मेशन टैक्नॉलजी के राज्यमंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा कि, इंडियन कम्प्यूटर एमरजैंसी रैस्पाँस टीम (सी.ई.आर.टी.-इन) के द्वारा की गई जांच के अनुसार ऐसा नहीं लगता कि कोविन ऐप या डेटा बेस को भेदा गया है।

विपक्षी दलों ने इस मामले में “अपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया तथा जांच की मांग की और पूछा कि सरकार डेटा प्रोटैक्शन कानून पर कुंडली मारकर क्यों बैठी है।

तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने अपने ट्विटर एकाउंट पर गोपनीयता भंग होने के स्क्रीन शॉट्स शेयर किए और कहा कि लीक हुए डेटा में वरिष्ठ नेताओं के आधार कार्ड नम्बर, पासपोर्ट नम्बर और वोटर आई.डी. का ब्यौरा तथा उनके परिजनों की जानकारी शामिल है। इन नेताओं में उनकी अपनी पार्टी के डैरेक ओ ब्रायन, पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और के.सी. वेणुगोपाल शामिल हैं।

ोमार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908